

भ्रष्टाचार पर आधार से लगाम

आधार के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में काफी मदद मिली है। महाराष्ट्र सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है। लेकिन जांच में पता चला कि वहां 30 से 40 फीसदी बच्चों की संख्या और शिक्षकों की 20 फीसदी संख्या कम हो गई है। दरअसल आधार को अनिवार्य बनाने के बाद फर्जीवाड़े का पता चला और इन बच्चों और शिक्षकों का अस्तित्व ही नहीं था जबकि इनके नाम पर लाभ लिया जाता था। हालांकि आधार डेटा के चोरी होने की शंकाओं के बाद मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। अदालत ने आधार की संवैधानिक वैधता जारी रखी लेकिन कुछ बदलाव भी किए।

दुर्गेश शर्मा, ईमेल से